International Journal of Economic Perspectives, 9(1) Dec 2015, PP: 79-84
Retrieved from: http://ijeponline.com/index.php/journal

ग्रामीण-शहरी प्रवास का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

रूप राज

सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार

सार: प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण-शहरी प्रवास के कुल और लिंग-वार कारणों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में लघु, मध्यम और लंबी दूरी के प्रवास-धाराओं में ग्रामीण-शहरी प्रवास के सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों पर भी प्रकाश डाला गया हैi प्रवासन लोगों का एक पारिस्थितिकी क्षेत्र से दूसरे पारिस्थितिकी क्षेत्र में जाना है; यह अस्थायी या स्थायी आधार पर हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाना प्रवासन की मुख्य श्रेणियों में से एक है और यह जनसांख्यिकीय संरचना की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण जनसंख्या पुनर्वितरण हुआ है। यह अध्ययन ग्रामीण-शहरी प्रवासन के कारणों पर केंद्रित है और ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर इसके प्रभावों की भी जांच करता है। यह पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब शैक्षिक सुविधाएं और रोजगार के अवसरों की कमी ग्रामीण-शहरी प्रवासन के पीछे मुख्य कारक हैं। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि ग्रामीण-शहरी प्रवासन के कारण ग्रामीणों की मजबूत सामुदायिक भावना और सामाजिक-नैतिक पहलुओं को चुनौती मिली है। हालांकि, दूसरी ओर, यह भी देखा गया है कि ग्रामीण-शहरी प्रवासन में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में जीवन स्तर में काफी हद तक सुधार हुआ है।

ग्रामीण-शहरी प्रवास और अनौपचारिक आवास

विकासशील देशों में ग्रामीण-शहरी प्रवास की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्र-राज्यों के उदय में हैं, जिसने उनके लिए तेजी से औद्योगिकीकरण के माध्यम से आधुनिकता हासिल करना अनिवार्य बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कस्बों और शहरों के पास तेजी से शहरीकरण हुआ, जहाँ ये उद्योग स्थित थे। इसके साथ ही कृषि कार्य का मशीनीकरण भी बढ़ा, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन किसानों को उद्योगों में काम की तलाश में शहरों में आने के लिए मजबूर किया। इसलिए, अधिकांश कम विकसित देशों में, तेजी से शहरीकरण ग्रामीण-शहरी प्रवास में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ था। एशिया और अफ्रीका के कई देशों में, यह भू-राजनीतिक स्थितियों की हिंसा और अस्थिरता के साथ भी जुड़ा हुआ था - औपनिवेशिक शासकों के हटने के कारण पहले के भौगोलिक क्षेत्रों का विभाजन, और उत्पीड़न से बचने के लिए बड़ी आबादी का शहरों की ओर पलायन।

© 2015 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 26Oct 2015, Revised: 09 Nov2015, Accepted: 15 Dec 2015

International Journal of Economic Perspectives, 9(1) Dec 2015, PP: 79-84
Retrieved from: http://ijeponline.com/index.php/journal

ग्रामीण-शहरी प्रवास को कई विद्वानों द्वारा 'धकेलने और खींचने' वाले कारकों के माध्यम से भी समझाया जाता है। धकेलने वाले कारक ग्रामीण क्षेत्रों से काम करते हैं, जहाँ फसल उत्पादन और आय में गिरावट के साथ-साथ ग्रामीण जमींदारों द्वारा भूमिहीन किसानों का शोषण बड़ी ग्रामीण आबादी को पास के शहरी केंद्रों में धकेलता हुआ देखा जाता है। खींचने वाले कारक शहर को आय और अवसरों के स्रोत के रूप में देखते हैं, जहाँ इसके निवासियों को उच्च आय, बेहतर रोजगार की स्थिति और इसलिए बेहतर जीवन मिलता है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश मामलों में, ग्रामीण आबादी जो शहरों में प्रवास करती है, अक्सर अकुशल आकस्मिक श्रमिकों या सेवा क्षेत्र में कार्यरत होती है, जिससे उन्हें औपचारिक आवास तक पहुँच नहीं मिलती है। 1970 के दशक के दौरान कम विकसित देशों में शहरीकरण की गति ने शहरी गरीबों, विशेष रूप से बड़े शहरों में रहने वालों को आवास समाधान के लिए अनौपचारिक बाजार की ओर देखने के लिए मजबूर किया। शहरी क्षेत्रों में अर्ध-स्थायी घरों की संख्या में उच्च वृद्धि से इसकी पुष्टि हुई, जो 1970 के दशक के दौरान कई शहरों के कुल आवास स्टॉक की तुलना में बहुत तेज़ थी। ग्रामीण प्रवासी मलिन बस्तियों और अवैध बस्तियों में केंद्रित होते थे , जहां पानी, सफाई, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं या अस्पताल या स्कूल जैसी सामाजिक सेवाएं नहीं होती थीं।

माइक डेविस (2006) विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देते हैं कि वैश्विक दक्षिण के शहरों में शहरीकरण और आर्थिक विकास के बीच विसंगति के कारण वेतन में गिरावट, कीमतों में उछाल और बढ़ती बेरोजगारी के परिणामस्वरूप 'अनौपचारिक शहरी सर्वहारा वर्ग' का उदय हुआ है। डेविस (2006) रॉय (2005) हमें याद दिलाते हैं, अनौपचारिक वास्तव में "राज्य द्वारा ही निर्मित" है। यह औपचारिक मानदंडों के जानबूझकर निलंबन का प्रतिनिधित्व करता है, और यह राज्य है जिसके पास "यह निर्धारित करने की शक्ति है कि इस निलंबन को कब लागू किया जाए, यह निर्धारित करने की शक्ति है कि क्या अनौपचारिक है और क्या नहीं है, और यह निर्धारित करने की शक्ति है कि अनौपचारिकता के कौन से रूप पनपेंगे और क्या नहीं" (रॉय, 2005 : 149)।यह 'राज्य के विश्वासघात' का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों की संरचनात्मक समायोजन नीतियों को अधिशेष ग्रामीण आबादी को शहरी झुग्गियों में धकेलने की अनुमति दी है, जबकि 'राज्य' नियमित रूप से "भूमि मालिकों, विदेशी निवेशकों, कुलीन गृहस्वामियों और मध्यम वर्ग के यात्रियों के लाभ के लिए स्थानिक सीमाओं को फिर से बनाने" के लिए हस्तक्षेप करता है (पृष्ठ 98)। इस प्रकार वैश्विक दक्षिण में झुग्गियों और अनौपचारिक आवास के अन्य रूपों को विशेष रूप से गरीबी, हाशिए पर होने और अशक्तता

© 2015 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 26Oct 2015, Revised: 09 Nov2015, Accepted: 15 Dec 2015

International Journal of Economic Perspectives, 9(1) Dec 2015, PP: 79-84
Retrieved from: http://ijeponline.com/index.php/journal

के विकासात्मक प्रवचनों से जोड़ा गया है; और बाद में संबंधित राष्ट्र-राज्यों और अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों की परस्पर विचारधाराओं और प्रथाओं से जोड़ा गया है।

पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण-शहरी प्रवास के परिणामस्वरूप कई तरह की अनौपचारिक आवास व्यवस्थाएं हुई हैं। रॉय और अलसय्यद (2004) सुझाव देते हैं कि इस तरह की 'शहरी अनौपचारिकता' में वे प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से वे लोग, जो आवास, आजीविका और बुनियादी सेवाओं तक कानूनी और औपचारिक पहुंच से बाहर हैं, अपनी स्थितियों को बदलने के लिए अनौपचारिक स्थानों का उपयोग करते हैं। यह तब होता है, जब ग्रामीण प्रवासी सार्वजनिक भूमि पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके एक अस्थायी घर बना लेते हैं। साओ पाओलो, ब्राजील या जोहान्सबर्ग जैसे शहरों में, ये शहरी परिधि में अवैध भूमि उपविभाजन का रूप ले लेते हैं; जबकि दिल्ली और मुंबई में, ये वाणिज्यिक और उच्च अंत वाले आवासीय क्षेत्रों के पास शहर के केंद्रों के भीतर अस्थायी झुग्गियों का रूप ले लेते हैं। हालिया प्रकाशन, *चैलेंज ऑफ द स्लम्स*रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग एक अरब लोग, जिनमें से ज़्यादातर शहर में प्रवासी हैं, झुग्गी-झोपड़ियों या अनौपचारिक आवास स्थितियों में रहते हैं , जो भीड़भाड़ , घटिया आवास और असुरक्षित आवास की विशेषता रखते हैं। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि "कुछ स्थानों - उदाहरण के लिए इथियोपिया, चाड, अफ़गानिस्तान और नेपाल - में 90% से ज़्यादा शहरी निवासी झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, जबकि चीन में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग शहरी आबादी का 37%, भारत में 55% , नाइजीरिया में 79% और बांग्लादेश में 84% हैं।"

1980 के दशक से अनौपचारिक आवास का उदय वैश्विक दक्षिण में नवउदारवादी राज्यों की विचारधाराओं और प्रथाओं से भी जुड़ा हुआ है, जो शहरी गरीबों को आवास देने के लिए बाजार-आधारित ताकतों पर निर्भर रहे हैं। इसके साथ ही शहरी मध्यम वर्ग का प्रभुत्व और दृश्यता उभरी है, जो बाजार के प्रमुख उपभोक्ता हैं और जो शहरी सार्वजनिक स्थान के सौंदर्यीकरण में तेजी से रुचि रखते हैं। अनौपचारिक आवास का अस्तित्व कई वैश्वीकृत शहरों की आकांक्षाओं के रास्ते में आता हुआ देखा जाता है - ऐसे स्थान जो 'अन्य' शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कार्यालयों, लक्जरी आवास, मेगामॉल और हाई-स्पीड परिवहन नेटवर्क के लिए असुविधाजनक भौतिक निकटता में स्थित हैं। भले ही उनके अधिकांश निवासी इन शहरों के दूसरी या तीसरी पीढ़ी के निवासी हैं, फिर भी उन्हें अनिवार्य रूप से ग्रामीण प्रवासियों के रूप में देखा जाता है, जिन्हें शहर में आवास का अधिकार नहीं है। हांगकांग , रियो डी

© 2015 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 26Oct 2015, Revised: 09 Nov2015, Accepted: 15 Dec 2015

International Journal of Economic Perspectives, 9(1) Dec 2015, PP: 79-84
Retrieved from: http://ijeponline.com/index.php/journal

जेनेरो, डकार, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों ने हाल ही में शहर के केंद्र से सैकड़ों हज़ारों अवैध निवासियों को बेदखल कर बाहरी इलाकों में भेज दिया है।

यह देखा गया है कि कई अनैच्छिक ताकतें हैं जो ग्रामीण परिवारों को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर करती हैं। वर्तमान अध्ययन में रोजगार, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है।

तालिका 1: ग्रामीण-शहरी प्रवास के प्रेरक कारक

क्र.सं.	पुश कारक	राय का पैमाना प्रतिशत में		
		Yes	No	Total
1.	ख़राब शैक्षणिक सुविधाएं	88.58	11.42	100
2.	रोजगार का अभाव	77.13	22.88	100
3.	कृषि में असफलता	45.72	54.28	100
4.	परिवहन एव सचार सुविधाएं	22.86	77.14	100

स्रोत: फ़ील्ड वर्क. 2016

भाली आनंदपुर (रोहतक) के अध्ययन से पता चलता है कि 85 उत्तरदाताओं में से 88.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि "खराब शैक्षिक सुविधाएं" पलायन के सबसे प्रमुख कारण हैं (तालिका 1)। साथ ही, 77.13 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि रोजगार की कमी है और 45.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कृषि में विफलता पर सहमति जताई, जबकि 22.86 प्रतिशत का मानना है कि परिवहन और संचार जैसी खराब बुनियादी सुविधाओं के कारण ही ग्रामीणों को कस्बों और शहरों की ओर जाना पड़ता है।

ग्रामीण-शहरी प्रवास के आकर्षण कारकों के अंतर्गत रोजगार, शिक्षा, आधुनिक शहरी सुविधाएं और सामाजिक संबंध जैसे कारकों को अध्ययन में लिया जाता है।

ये कारक भी भाली आनंदपुर (रोहतक) गांव में ग्रामीणों को गांव से कस्बों और शहरों की ओर खींच रहे हैं। अध्ययन से, यह देखा गया है कि 85 उत्तरदाताओं में से 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बच्चों की शिक्षा और करियर विकास ने उन्हें कस्बों और शहरों में खींच लिया है (तालिका 2)। साथ ही, 74.28 प्रतिशत ने कहा है कि वे रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरों में चले गए। शहरी कस्बों में आधुनिक सुविधाओं के विकास ने भी ग्रामीणों को पलायन करने के लिए आकर्षित किया है और 42.85 प्रतिशत का मानना है कि यह फिरो ग्रामीणों के बीच पलायन का एक कारण है, जबकि 51.42 प्रतिशत सामाजिक कारकों जैसे शहरी क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के कारण गांव से चले गए।

© 2015 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 26Oct 2015, Revised: 09 Nov2015, Accepted: 15 Dec 2015

International Journal of Economic Perspectives, 9(1) Dec 2015, PP: 79-84
Retrieved from: http://ijeponline.com/index.php/journal

तालिका 2: भाली आनंदपुर गांव में ग्रामीण-शहरी प्रवास के आकर्षण कारक

क्र.सं.	पुश कारक	राय का पैमाना प्रतिशत में		
		Yes	No	Total
1.	बच्चों की शिक्षा और करियर	80.00	20.00	100
2.	रोजगार की तलाश	74.28	25.72	100
3.	प्रशिक्षण और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम	60.00	40.00	100
4.	रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ना	51.42	48.58	100
5.	आधुनिक शहरी सुविधाएँ	42.85	58.15	100

स्रोत: फ़ील्ड वर्क. 2016

ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव एक जटिल और बहुआयामी विषय है। यह प्रवास अनेक कारणों से होता है, जिसमें आर्थिक अवसर, बेहतर जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि शामिल हैं.

सामाजिक प्रभाव:

- सामाजिक संरचना में बदलाव:

  शहरी क्षेत्रों में प्रवास से सामाजिक संरचना में बदलाव आते हैं। लोग नए लोगों से मिलते हैं, नई संस्कृतियों से परिचित होते हैं, और सामाजिक संबंध बदलते हैं.

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान:

  ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग अपने साथ अपनी संस्कृति, भाषा और रीति-रिवाजों को लाते हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है.

- सामाजिक असमानता:

  प्रवास से सामाजिक असमानता भी बढ़ सकती है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अधिक धन और संसाधनों का लाभ उठाते हैं.

- सामाजिक तनाव:

  शहरों में बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव से सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है.

आर्थिक प्रभाव:

- आर्थिक वृद्धि:

  शहरी क्षेत्रों में प्रवास से आर्थिक वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इससे श्रम शक्ति में वृद्धि होती है और शहरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है.

© 2015 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 26Oct 2015, Revised: 09 Nov2015, Accepted: 15 Dec 2015

International Journal of Economic Perspectives, 9(1) Dec 2015, PP: 79-84
Retrieved from: http://ijeponline.com/index.php/journal

- **रोजगार के अवसर:**

  शहरों में प्रवास से लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है.

- **बेहतर जीवन स्तर:**

  ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेहतर जीवन स्तर होता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और सामाजिक सुविधाएँ.

- **सामाजिक सुरक्षा:**

  शहरी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा के उपाय अधिक होते हैं, जैसे कि पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, और स्वास्थ्य बीमा.

- **नकारात्मक प्रभाव:**

  प्रवास से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव, और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति की कमी.

निष्कर्ष: ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जटिल और बहुआयामी है। यह प्रवास सामाजिक संरचना में बदलाव, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सामाजिक असमानता, सामाजिक तनाव, आर्थिक वृद्धि, रोजगार के अवसर, बेहतर जीवन स्तर, और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। यह प्रवास कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है.

References:

- Antman, F.M. (2013). "The impact of migration on family left behind". International Handbook on the economics of migration, 2013. IZA Discussion papers, No. 6374. Socio-Economic Impact of Rural-Urban Migration
- Aier, A. and Kithan, T. (2011). Rural-Urban Migration: A Thematic Report 2009, Department of Planning and Coordination, Government of Nagaland.
- Becker, G.S. (1965). "A Theory of the Allocation of Time." The Economic Journal, Vol. 75, No. 299 (Sept., 1965), 493-517.
- Census of India, 2011.
- Everett, S.L. (1966). "A Theory of Migration." Demography, Vol. 3, No. 1., pp. 47-57.
- Ezung, Z.T. (2015). "Issues of Migration in Nagaland." International Journal of Social Science, Vol. 4, No. 1, March 2015, pp. 81-87.
- Kuhn, R.S, Everett and Silvey, R. (2011). "The effects of children's migration on elderly kin's health: A counterfactual approach", Demography, 48(1): 183-209.
- Longchar, M. (2014). "Rural-Urban Migration and its Impact on the Urban Environment and Life in Nagaland", Nagaland Transactions, Vol. 36, No. 1, 2014, pp.102-105.

© 2015 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 26Oct 2015, Revised: 09 Nov2015, Accepted: 15 Dec 2015